नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 027
दि. 30.10.2025,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

चक्रवात 'मोन्था' ने मचाई दक्षिण भारत में भीषण तबाही, हजारों लोग बेघर, फसलें बर्बाद, ट्रेनें ठप

(जीएनएस)। महबूबाबाद। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात 'मोन्था' मंगलवार रात जब आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट से टकराया, तो उसने दक्षिण भारत के कई राज्यों में तबाही मचा दी। लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने तटीय इलाकों को झकझोर दिया। कई जिलों में झमाझम बारिश ने जनजीवन ठप कर दिया, सड़कों पर जलभराव हो गया और बिजली आपूर्ति ठप हो गई। महबूबाबाद जिले के डोरनकल रेलवे स्टेशन पर पानी भर जाने से ट्रेनों की आवाजाही रुक गई। गोलकुंडा एक्सप्रेस और कोणार्क एक्सप्रेस को बीच रास्ते में रोकना पड़ा। नालगोंडा जिले में एक स्कूल पूरी तरह जलमग्न हो गया, लेकिन बच्चों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं खम्मम जिले में एक ट्रक पानी के तेज बहाव में बह गया। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, तट पार करने के बाद तूफान कमजोर पड़ गया है और अब यह साधारण चक्रवाती तूफान में बदल गया है, जो उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों विजयवाड़ा, राजामुंद्री और पश्चिम गोदावरी में भारी बारिश से सड़कों पर नदियां बहने लगीं। पेड़ उखड़ गए और सैकड़ों गांवों में बिजली की तारें टूट गईं। राज्य सरकार ने बताया कि अब तक लगभग 76,000 लोगों को राहत शिविरों में सुरक्षित पहुंचाया गया है। 219 मेडिकल कैंप बनाए गए हैं और आपात स्थिति से निपटने के लिए 488 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। राहत कार्यों के लिए 1,447 अर्थमूवर, 321 ड्रोन और 1,040 चेनसॉ मशीनें तैनात की गई हैं। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार,

चक्रवात 'मोन्था' ने कृषि को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। लगभग 38,000 हेक्टेयर कृषि फसलें और 1.38 लाख हेक्टेयर बागवानी फसलें बर्बाद हो गई हैं। नारियल, केला और पपीते की फसलें पूरी तरह तबाह हो गईं। कई गांवों में मकान ढह गए, पशुधन बह गया और ग्रामीणों को रातभर राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने सभी जिलाधिकारियों को प्रभावित इलाकों में तत्काल राहत सामग्री पहुंचाने के निर्देश दिए हैं और नुकसान का आकलन करने के लिए विशेष टीमें गठित की हैं। तूफान का असर पड़ोसी राज्य ओडिशा में भी देखने को मिला। ओडिशा के दक्षिणी जिलों गंजाम, गजपति, कोरापुट और मलकानगिरी में तेज हवाओं और भारी बारिश ने कहर बरपाया। कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ और सड़कें टूट गईं। पुलों पर यातायात रोक दिया गया। ओडिशा के 15 जिलों में सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों को निचले इलाकों से हटने की सलाह दी है। वहीं पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के चंदननगर में भी तूफान का असर दिखा। जगद्धात्री पूजा के दौरान लगभग 70 फीट ऊंचा पंडाल गिर गया, जिससे सात लोग घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और स्थानीय प्रशासन ने आयोजकों के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया है।

भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि अगले 24 घंटों में यह चक्रवात और कमजोर होकर 'डीप डिप्रेशन' में तब्दील हो जाएगा। हालांकि आंध्र प्रदेश, दक्षिण ओडिशा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में अभी भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। भुवनेश्वर मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. संजीव द्विवेदी ने कहा कि लैंडफॉल प्रक्रिया अभी जारी है और तूफान लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि कुछ इलाकों में 20 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है, जिससे निचले क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो सकती है।

चक्रवात 'मोन्था' ने दक्षिण भारत में तबाही के गहरे निशान छोड़ दिए हैं। तटीय घरों के मलबे, उखड़े पेड़ों, बर्बाद फसलों और डूबी सड़कों के बीच लोग अब धीरे-धीरे अपने जीवन को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन की राहत टीमें लगातार काम में जुटी हैं, लेकिन लोगों के चेहरों पर अभी भी भय और अनिश्चितता साफ झलक रही है।

पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे के घर सेंध — गहनों के साथ 'राजदार सीडी' और पेन ड्राइव गायब, सियासी हलचल तेज

(जीएनएस)। जलगांव। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे के घर में हुई चोरी ने पूरे राज्य के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। खडसे ने इस घटना को साधारण चोरी नहीं, बल्कि राजनीतिक साजिश बताया है। चोरी में न केवल नकदी और गहने बल्कि वे दस्तावेज, सीडी और पेन ड्राइव भी गायब हैं जिनमें कथित रूप से कई नेताओं से जुड़े 'गोपनीय' सबूत होने की बात कही जाती रही है। घटना जलगांव के शिवराम नगर इलाके में स्थित खडसे के निवास पर दो रात पहले हुई। पुलिस के अनुसार, अज्ञात चोर देर रात करीब एक बजे घर में घुसे और लगभग एक घंटे तक बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज में तीन लोगों की परछाइयां दिखी हैं, जो पूरी योजना के साथ भीतर दाखिल हुए और गहनों के साथ कई महत्वपूर्ण वस्तुएं ले गए। चोरी गए सामान में लगभग सात से आठ तोला सोना, करीब 35 हजार रुपए नकद, दस सीडी, तीस पेन ड्राइव और कई संवेदनशील फाइलें शामिल हैं। खडसे ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, "यह सिर्फ चोरी नहीं, यह एक राजनीतिक वार है। जिन लोगों को मेरे पास मौजूद दस्तावेजों से डर था, वही इस घटना के पीछे हैं।" उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले उन्हें धमकी भी मिली थी कि "सीडी और पेन ड्राइव गायब कर दी जाएंगी।" खडसे ने हालांकि किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि यह पूरी वारदात 'सोची-समझी साजिश' का हिस्सा है। उन्होंने सवाल उठाया, "अगर चोरों का मकसद सिर्फ पैसा या गहना होता, तो वे बाकी सामान छोड़कर सिर्फ वही चीजें क्यों ले जाते जिनका राजनीतिक महत्व है?" खडसे के मुताबिक, चोरों ने घर के उस हिस्से को खासतौर पर निशाना बनाया जहां दस्तावेज रखे गए थे। यह पहली बार नहीं है जब खडसे परिवार पर इस तरह की घटना हुई हो। पिछले कुछ वर्षों में उनके परिवार को कई बार निशाना बनाया जा चुका है। कुछ साल पहले उनकी बहू और केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे के पेट्रोल पंप पर हथियारबंद डकैती हुई थी। वहीं, उनकी बेटी रोहिणी खडसे के पति प्रज्वल खेवलकर को एक कथित रेव पार्टी केस में गिरफ्तार किया गया था। इन घटनाओं के बाद अब यह चोरी उनके परिवार को एक बार फिर सुर्खियों में ले आई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जलगांव पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और स्थानीय अपराध शाखा की टीम जांच में लगी हुई है। प्रारंभिक जांच में किसी 'इनसाइडर' की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि घर के अंदर की जानकारी रखने वाले ही इतनी सटीक वारदात कर सकते हैं। राजनीतिक हलकों में इस घटना ने बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। खडसे कभी महाराष्ट्र बीजेपी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते थे, लेकिन 2014 के बाद पार्टी से किनारा कर उन्होंने शरद पवार का दामन थाम लिया। इसके बाद से उनकी और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच तल्खी जगजाहिर रही। उन्होंने कई बार यह दावा भी किया था कि उनके पास ऐसी "सीडी और सबूत" हैं जो कई बड़े नेताओं का राजनीतिक करियर खत्म कर सकते हैं। अब उन्हीं सीडी और पेन ड्राइव के चोरी हो जाने से राजनीतिक अटकलों का बाजार गर्म है। भाजपा और एनसीपी (शरद पवार गुट) दोनों के खेमों में चर्चा का दौर चल रहा है कि आखिर उन स्टोरेज डिवाइसों में क्या था — और क्या यह चोरी एक बड़े खुलासे को रोकने के लिए की गई?

नागपुर में किसानों का 'महा एल्गार मार्च'— 30 किलोमीटर लंबा जाम, अदालत के आदेश के बावजूद नहीं हटे प्रदर्शनकारी

(जीएनएस)। नागपुर। महाराष्ट्र के नागपुर-वर्धा राजमार्ग पर बुधवार को किसान आंदोलन के चलते हालात बिगड़ गए। बच्चू कडू के नेतृत्व में हजारों किसानों के 'महा एल्गार मार्च' ने पूरे क्षेत्र में यातायात को ठप कर दिया। प्रदर्शन इतना बड़ा था कि नागपुर-वर्धा मार्ग (NH-44) पर करीब 30 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे आमजन को भारी परेशानी झेलनी पड़ी।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस प्रदर्शन पर स्वतः संज्ञान लेते हुए बुधवार शाम छह बजे तक हाईवे खाली करने का आदेश दिया था। लेकिन आदेश के बावजूद किसान सड़क पर डटे रहे। शाम को पुलिस ने धरना स्थल पर पहुंचकर अदालत का आदेश बच्चू कडू को दिखाया। इस पर कडू ने कहा कि वे अदालत का अपमान नहीं करेंगे, लेकिन तब तक हटेंगे नहीं जब तक उनकी गिरफ्तारी की व्यवस्था नहीं होती। उन्होंने कहा, "हम अपनी मर्जी से नहीं जाएंगे, सरकार चाहे तो हमें जेल भेज दे, पर किसान की आवाज नहीं दबेगी।"

सरकार ने स्थिति संभालने के लिए बातचीत का रास्ता चुना। देर शाम राज्य सरकार की ओर से मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले और अन्य अधिकारी धरना स्थल पर पहुंचे और बच्चू कडू से संवाद किया। किसान नेताओं ने स्पष्ट किया कि जब तक राज्य सरकार कर्ज माफी, फसल बोनस और सूखा राहत पर ठोस घोषणा नहीं करती, तब तक वे आंदोलन खत्म नहीं करेंगे।

यह आंदोलन दरअसल राज्य सरकार से किए गए पुराने वादों को पूरा करने की मांग को लेकर शुरू हुआ है। पूर्व मंत्री और प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कडू ने मंगलवार को नागपुर से विशाल ट्रैक्टर मोर्चा निकालकर चेतावनी दी थी कि यदि किसानों की मांगें नहीं मानी गईं तो वे हाईवे जाम कर देंगे। बुधवार को उन्होंने अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतरकर यही किया।

बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस रजनीश व्यास ने सुनवाई के दौरान कहा कि प्रदर्शन की अनुमति केवल 24 घंटे के लिए थी, इसलिए आंदोलनकारियों को शाम छह बजे तक सड़क खाली करनी चाहिए। लेकिन अदालत के आदेश से पहले ही हजारों किसान जामठा फ्लाईओवर से लेकर वर्धा रोड तक फैल चुके थे, जिसके कारण ट्रैफिक पूरी तरह थम गया। एंबुलेंस और यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों से भेजना पड़ा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस स्थिति पर कहा कि सरकार संवाद के जरिए ही समाधान चाहती है। उन्होंने कहा कि "आंदोलन समाधान नहीं है, बातचीत ही रास्ता है।" फडणवीस ने बताया कि सरकार ने पहले भी बच्चू कडू और उनके प्रतिनिधियों को मीटिंग के लिए बुलाया था, लेकिन वे शामिल नहीं हुए। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि किसानों की वास्तविक समस्याओं पर ठोस कार्रवाई की जाएगी।

किसान नेता बच्चू कडू ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि "पिछले एक साल में सूखा, ओलावृष्टि और प्राकृतिक आपदाओं ने किसानों की कमर तोड़ दी है, लेकिन मुआवजा अधूरा और अपूर्ण है। बैंक किसान की जमीन नीलाम कर रहे हैं, जबकि सरकार सिर्फ वादे कर रही है।"

स्वाभिमानी शेतकरी संघटना के नेता रवीकांत तुपकर ने भी कहा कि "हाईवे और मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए हजारों करोड़ रुपए हैं, लेकिन किसानों के कर्ज माफ करने के लिए नहीं। अगर सरकार ने जल्द राहत नहीं दी तो यह आंदोलन पूरे महाराष्ट्र में फैलेगा।" बुधवार शाम तक स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में रही। पुलिस ने धारा 144 लागू कर रखी थी और भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया था। हालांकि देर रात तक बातचीत जारी थी, लेकिन किसान नेता अपने रुख पर अडिग रहे। नागपुर-वर्धा हाइवे पर ट्रैफिक रात तक प्रभावित रहा, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा।

इस आंदोलन ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या महाराष्ट्र सरकार किसानों के आर्थिक संकट को लेकर गंभीर है, या फिर वादों और रिपोर्टों के बीच किसानों की पीड़ा एक बार फिर राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाएगी।

दाऊद के ड्रग्स सिंडिकेट का खुलासा, एनसीबी ने मुख्य ऑपरेटर दानिश मर्चेंट और पत्नी हिना शाह को गोवा से दबोचा

(जीएनएस)। मुंबई। भारत की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम के ड्रग्स नेटवर्क पर एक बड़ा प्रहार किया है। एजेंसी ने मुंबई से संचालित अंतरराज्यीय ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए दाऊद के करीबी सहयोगी दानिश चिकना उर्फ दानिश मर्चेंट और उसकी पत्नी हिना शाह को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों देश में मफेड्रोन (MD) और अन्य सिंथेटिक ड्रग्स की तस्करी कर दाऊद गिरोह के लिए वित्तीय नेटवर्क तैयार कर रहे थे। एनसीबी को कुछ हफ्ते पहले गुप्त सूचना मिली थी कि पुणे में एमडी ड्रग्स की एक बड़ी खेप पहुंचने वाली है। इस आधार पर एजेंसी ने जाल बिछाकर एन. गायकवाड़ नामक तस्कर को पकड़ा, जिसके पास से 502 ग्राम मफेड्रोन बरामद हुआ। पूछताछ के दौरान उसने कबूला कि यह ड्रग्स सप्लाई मुंबई से होती है और उसके ऊपर "दानिश" नाम का एक व्यक्ति काम करवाता है।

इस जानकारी के बाद एनसीबी की टीम मुंबई पहुंची और बांद्रा इलाके में छापेमारी की। यहां से 839 ग्राम मफेड्रोन जब्त की गई और मौके से एक आरोपी जोहैब शेख गिरफ्तार हुआ। उसने पूछताछ में खुलासा किया कि यह सारा कारोबार दानिश मर्चेंट और उसकी पत्नी हिना शाह के इशारे पर चलता है, जो मुंबई से नेटवर्क को नियंत्रित करते हैं।

इसके बाद एनसीबी ने कई राज्यों में खुफिया निगरानी अभियान चलाया। जांच में पता चला कि दानिश और हिना लगातार ठिकाने, मोबाइल

नंबर और वाहन बदलते हुए फरारी काट रहे थे। आखिरकार 25 अक्टूबर 2025 को एजेंसी ने गोवा के एक लग्जरी रिजॉर्ट से दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान उनके पास से कई मोबाइल, लैपटॉप, विदेशी करेंसी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच से कई और बड़े नाम सामने आने की संभावना जताई जा रही है।

एनसीबी अधिकारियों के मुताबिक, दानिश मर्चेंट दाऊद इब्राहिम के ड्रग्स सिंडिकेट का अहम हिस्सा था। वह मुंबई, पुणे, राजस्थान और गोवा में ड्रग्स सप्लाई चेन को संभालता था। तस्करी से होने वाली कमाई हवाला के जरिए दुबई और पाकिस्तान तक पहुंचाई जाती थी। एजेंसी को संदेह है कि यह नेटवर्क दक्षिण अफ्रीका और मलेशिया तक फैला हुआ है।

दानिश का आपराधिक रिकॉर्ड भी लंबा है। वह मुंबई के डोंगरी इलाके का कुख्यात ड्रग्स तस्कर माना जाता है। 2021 में एनसीबी ने उसे कोकीन और गांजा तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया था, जबकि राजस्थान पुलिस ने भी उसी साल उसके खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। 2024 में मुंबई पुलिस ने उसे सिंथेटिक ड्रग्स बनाने के आरोप में पकड़ा था और उसके खिलाफ कुल सात अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसकी पत्नी हिना शाह भी ड्रग्स तस्करी में सक्रिय रही है और वितरण से लेकर छिपाने तक के नेटवर्क में उसकी अहम भूमिका बताई जा रही है।

एनसीबी ने बताया कि इस गिरोह के तार दाऊद इब्राहिम के पुराने नेटवर्क से जुड़े हैं, जिनके जरिए ड्रग्स की तस्करी के साथ-साथ अवैध धन को विदेशों में पहुंचाया जाता था। अधिकारियों का कहना है कि इस गिरफ्तारी से अंडरवर्ल्ड के आर्थिक ढांचे को बड़ा झटका लगा है और एजेंसी आने वाले दिनों में नेटवर्क के अन्य सदस्यों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में है।

भारत की यह कार्रवाई न केवल ड्रग्स तस्करी के खिलाफ बल्कि अंडरवर्ल्ड के उस छिपे हुए नेटवर्क पर भी प्रहार है जो वर्षों से देश की युवा पीढ़ी को नशे के जाल में फंसा रहा था। दानिश और हिना की गिरफ्तारी इस बात का संकेत है कि अब एजेंसियां दाऊद गिरोह के आर्थिक स्तंभों को जड़ से खत्म करने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा चुकी हैं।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

बिहार प्रक्रिया के निष्कर्ष राह दिखाएंगे

उम्मीद के अनुरूप चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दूसरे चरण की विधिवत शुरुआत कर दी है। इस चरण में देश के नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के तकरीब 51 करोड़ मतदाता शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिये केवल तीन माह का समय दिया है। लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार में एसआईआर पर लंबे समय से चले विवादों के मद्देनजर, इस प्रक्रिया को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। खासकर उन राज्यों में जहां विपक्षी दल शासित सरकारें हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु व महाराष्ट्र से ऐसी प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो गई है। इसमें दो राय नहीं कि किसी भी लोकतंत्र में पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के लिये जरूरी है कि पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में निश्चित रूप से शामिल किया जाना चाहिए। वहीं अयोग्य मतदाता को हटाना सुनिश्चित करने के उद्देश्य को लेकर कोई विवाद नहीं माना जा सकता। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान विपक्षी दलों की तीखी प्रतिक्रिया के मद्देनजर पूरी प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही तत्काल सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इस बाबत मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि आगामी एसआईआर का लक्ष्य मतदाता सूचियों की लंबे समय से लंबित राष्ट्रव्यापी सफाई करना है। ऐसे व्यापक संशोधन देश में समय-समय पर हुए हैं और पिछला संशोधन दो दशक पहले हुआ था। जाहिर बात है कि इस लंबे अंतराल के दौरान मतदाता सूचियों में कई विसंगतियां और त्रुटियां उत्पन्न हो गई होंगी। आयोग ने उदाहरण देते हुए कहा है कि प्रशांत किशोर बिहार के साथ-साथ पश्चिम बंगाल में भी मतदाता के रूप में सूचीबद्ध हैं। देश में निष्पक्ष चुनाव के लिये इन सूचियों का प्रमाणीकरण अपेक्षित है। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष दलों की आशंकाओं की अनदेखी भी नहीं की जानी चाहिए। साथ ही लोगों में लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया के प्रति उत्साह बना रहना भी जरूरी है।

दरअसल, कांग्रेस, माकपा, तृणमूल कांग्रेस आदि दलों को आशंका है कि एसआईआर का इस्तेमाल अवैध मतदाताओं की पहचान की आड़ में लक्षित वास्तविक मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने के लिये हो सकता है। वैसे बिहार में हुई कवायद के बाद ज्ञात नहीं है कि यह प्रक्रिया कितने अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने में सफल रही है। निस्संदेह, चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा उचित प्रक्रिया-परिश्रम और जनता के विश्वास पर ही टिकी है। निर्विवाद रूप से देश में चुनाव कराने वाली शीर्ष संवैधानिक संस्था की ईमानदारी और निष्पक्षता दोषमुक्त होनी ही चाहिए। चुनाव आयोग को व्यापक सत्यापन, इस प्रक्रिया से जुड़े तमाम हितधारकों के साथ विमर्श और वास्तविक मतदाताओं के मताधिकार को अक्षुण्ण बनाने हेतु एक ठोस निवारण तंत्र विकसित करने की जरूरत है। विपक्षी दलों द्वारा वोट चोरी और अन्य अनियमितताओं के कथित आरोपों का खंडन ठोस सबूतों के साथ किया जाना चाहिए। ताकि जनता में इस प्रक्रिया को लेकर भरोसा कायम रह सके। वैसे एसआईआर के दूसरे चरण का सकारात्मक पक्ष यह जरूर है कि आयोग ने प्रक्रिया के लिये पर्याप्त समय दिया है ताकि बिहार जैसी जल्दबाजी और अफरातफरी के आक्षेपों से बचा जा सके। निश्चित रूप से आधार कार्ड को सहायक दस्तावेज के रूप में मान्यता देने का लाभ प्रक्रिया के सरलीकरण में मिलेगा। विश्वास किया जाना चाहिए कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान सामने आई चुनौतियां इस दूसरे चरण की प्रक्रिया में मार्गदर्शक का कार्य करेंगी। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि दूसरे चरण में शामिल राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के लोगों को वैसी परेशानी का सामना न करना पड़े, जैसी कि बिहार के लोगों में सामने आई थी। लेकिन इसके साथ यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि योग्य मतदाता न छूटे और कोई फर्जी मतदाता लिस्ट में शामिल न होने पाए। यहां उल्लेखनीय है कि जिन राज्यों में दूसरे चरण के दौरान मतदाता सूचियों को गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया से गुजरना है, उनमें से कुछ में अगले साल चुनाव होने हैं। इनमें पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु व पुडुचेरी शामिल हैं। बहरहाल, कोशिश हो कि न ही जनता को परेशानी उठानी पड़े और न ही चुनाव कर्मियों में भ्रम जैसी स्थिति बनी रहे।

आगे जाता आसियान और पीछे होता सार्क

> दक्षिण एशिया का शुमार दुनिया के सबसे पिछड़े इलाकों में होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के प्रयासों में लगने वाले राजनीतिक अड़ंगे। इस इलाके का सहयोग संगठन दक्षेस खामोश है। नवंबर, 2014 में काठमांडू के शिखर सम्मेलन के बाद से उसका कोई सम्मेलन नहीं हुआ है।

हाल में दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया को लेकर दो तरह की खबरें मिली थीं, जिनसे दो तरह की प्रवृत्तियों के संकेत मिलते हैं। आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से और विदेशमंत्री एस जयशंकर स्वयं उपस्थित हुए थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कम्युनिटी विज़न 2045 को अपनाने के लिए आसियान की सराहना की। कम्युनिटी विज़न 2045 अगले बीस वर्षों में इस क्षेत्र को एक समेकित समन्वित विकास-क्षेत्र में तब्दील करने की योजना है।

अपने आसपास के राजनीतिक माहौल को देखते हुए यह ज़ाहिर होता जा रहा है कि भारत को पूर्व की दिशा में अपनी कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार करना होगा। यह विस्तार हो भी रहा है, पर म्यांमार की अस्थिरता और बांग्लादेश की अनिश्चित राजनीति के कारण कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। दक्षिण-पूर्व एशिया के पांच देशों (कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम) के साथ सांस्कृतिक और वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ावा देने वाले 'गंगा-मीकांग सहयोग कार्यक्रम' में हमें तेजी लानी चाहिए।

अब उस दूसरी खबर की ओर आएं, जो इस सिलसिले में महत्वपूर्ण है। भारत के सरकारी स्वामित्व वाले भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने गत 22 अक्तूबर से अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बांग्लादेश से इंटरनेट बैंडविड्थ का आयात बंद कर दिया। इस कदम का सीधा असर पूर्वोत्तर की इंटरनेट कनेक्टिविटी पर पड़ेगा, जो अभी तक बांग्लादेश अखौरा बंदरगाह के माध्यम से आयातित बैंडविड्थ पर निर्भर थी।

यह फैसला अचानक नहीं हुआ है। पिछले साल दिसंबर में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हसीना सरकार के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें भारत के पूर्वोत्तर को बैंडविड्थ की आपूर्ति के लिए बांग्लादेश को ट्रांज़िट प्वाइंट के रूप में उपयोग करने की अनुमति

दी गई थी। बांग्लादेश टेलीकम्युनिकेशंस रेग्युलेटरी कमीशन (बीटीआरसी) का कहना था कि भारत को ट्रांज़िट पॉइंट देने से क्षेत्रीय इंटरनेट हब बनने की हमारी क्षमता कमज़ोर हो जाएगी।

भारत का पूर्वोत्तर पहले घरेलू फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क का उपयोग करके चेन्नई में समुद्री केबलों के माध्यम से सिंगापुर से जुड़ा हुआ था। चूंकि चेन्नई में लैंडिंग स्टेशन पूर्वोत्तर से लगभग 5,500 किमी दूर है, इसलिए इंटरनेट की गति पर असर पड़ता था।

बहरहाल अब भारत पूर्वोत्तर राज्यों में इंटरनेट कनेक्शन पूरी तरह से अपने फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क और नए सैटेलाइट सिस्टम के जरिए देगा। इसके लिए भारतनेट प्रोजेक्ट में बड़े सुधार किए गए हैं, जो भारत का अपना डिजिटल नेटवर्क है। साथ ही इसरो के हाई-स्पीड सैटेलाइट नेटवर्क को भी बेहतर तरीके से जोड़ा गया है। इन बदलावों की वजह से अब पूर्वोत्तर राज्यों को तेज और भरोसेमंद इंटरनेट मिलेगा, बिना किसी बाहरी देश पर निर्भरता जताए हुए। भारत और बांग्लादेश के बीच यह महत्वपूर्ण सहयोग था, जो दक्षिण एशिया में कनेक्टिविटी के महत्व को रेखांकित करता था। यह सहयोग भी एकतरफा नहीं था। भारत भी बांग्लादेश को बैंडविड्थ दे रहा है, जिसे बांग्लादेश अब कम करता जा रहा है। बांग्लादेश ने दूसरे देशों, जैसे सिंगापुर वगैरह से समुद्र में बिछे केबलों के मार्फत बैंडविड्थ आयात शुरू किया है। बात केवल यह नहीं है कि वे अपनी बैंडविड्थ को बढ़ा रहे हैं, महत्वपूर्ण है भारत की अनदेखी करना।

इस साल 5 अगस्त को बांग्लादेश में छात्रों के विद्रोह के बाद शेख हसीना की सरकार के पराभव का एक साल पूरा हो गया है। इस दौरान वहां की अंतरिम सरकार बड़े-बड़े फैसले कर रही है, जिनमें कनेक्टिविटी, व्यापार और यहां तक कि रक्षा से जुड़े विषय भी शामिल हैं। हालांकि वहां अगले साल फरवरी में चुनाव कराने की घोषणा की गई है, पर एक तबका अब भी चाहता है कि चुनाव टाले जाएं और अंतरिम सरकार न केवल नीतियों के मामले में बल्कि संविधान से जुड़े मामलों में भी बुनियादी फैसले करे।

पिछले साल तक भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' और 'एक्ट ईस्ट' नीतियों के मूल में, बांग्लादेश एशिया में शीर्ष पांच निर्यात स्थलों में से एक और भारत के पर्यटन निर्यात का सबसे बड़ा स्रोत था। यह नई दिल्ली की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी महत्वाकांक्षाओं में भी एक महत्वपूर्ण कड़ी थी, जिसमें सड़क, रेल, ऊर्जा और डिजिटल नेटवर्क को एक इच्छुक भागीदार के रूप में ढाका के साथ सीमाओं के पार एक साथ जोड़ा गया था। राजनीतिक बदलाव ने इस यात्रा को रोककर विपरीत दिशा में बढ़ाना शुरू कर दिया है। व्यापार और ट्रांसशिपमेंट अधिकारों को निलंबित करने के साथ कनेक्टिविटी संपर्क बाधित हो गए हैं। इतना ही नहीं चीन-पाक से रिश्ते सुधारने की दिशा में इस देश ने असाधारण तेजी दिखाई है। भारत के साथ रेलवे लाइनों जैसी भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी परियोजनाओं को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया गया है। इसकी शिकार भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन (आईबीएफपी) भी हुई है। भारत-बांग्लादेश मैत्री उपग्रह-कार्यक्रम ठंडे बस्ते में चला गया है। ऐसे तमाम दूसरे कार्यक्रम रोक दिए गए हैं। यात्री ट्रेनों के निलंबन ने द्विपक्षीय रिश्तों के सबसे मूल्यवान उपकरण-जनता के संपर्क को तोड़ा है। बांग्लादेश के लोग इलाज के लिए भारत आते थे, उन्हें चीन की दिशा में मोड़ा जा रहा है। घटनाक्रम रेखांकित करता है कि दक्षिण एशिया में सीमा पार कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण किस हद तक राजनीतिक हवा पर निर्भर करते हैं।

मार्च, 2025 में चीन की यात्रा के दौरान बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को भूमि से घिरा हुआ बताया और बांग्लादेश को 'इस पूरे क्षेत्र में महासागर का एकमात्र संरक्षक' घोषित किया था। अप्रैल में, भारत ने भारतीय क्षेत्र से पारगमन करने वाले बांग्लादेशी सामानों को पहले दिए गए ट्रांसशिपमेंट अधिकारों को वापस ले लिया। मई में खबरें आईं कि भारतीय सीमा से महज 12 किलोमीटर दूर लालमोनिरहाट में एक पुराने हवाई अड्डे को चीन की मदद से बांग्लादेश पुनर्जीवित करने जा रहा है। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी समस्या कनेक्टिविटी की है। ऐतिहासिक रूप से यह इलाका कभी आपस में अच्छी तरह जुड़ा हुआ था, पर अब नहीं है। इन देशों में कनेक्टिविटी परिवहन (जैसे समुद्री मार्ग, सड़क और रेल), व्यापार और डिजिटल माध्यमों (जैसे उपग्रह) के माध्यम से बेहतर की जा सकती है। इस समय इन देशों के बीच अंतर-क्षेत्रीय व्यापार दुनिया में सबसे कम है, जो एकीकरण की कमी को दर्शाता है। दक्षिण एशिया का शुमार दुनिया के सबसे पिछड़े इलाकों में होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के प्रयासों में लगने वाले राजनीतिक अड़ंगे। इस इलाके का सहयोग संगठन दक्षेस खामोश है। नवंबर, 2014 में काठमांडू के शिखर सम्मेलन के बाद से उसका कोई सम्मेलन नहीं हुआ है। उस सम्मेलन में दक्षेस देशों के मोटर वाहन और रेल संपर्क समझौते पर सहमति नहीं बनी, जबकि पाकिस्तान को छोड़ सभी देश इसके लिए तैयार थे। नवाज़ शरीफ के नेतृत्व में वहां की सरकार भी समझौते के पक्ष में दिखाई पड़ती थी, पर अंतिम क्षणों में वहां की सेना ने वह समझौता नहीं होने दिया।

भारत ने दक्षिण एशियाई उपग्रह परियोजनाओं की पेशकश की, जिसमें शामिल होने से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। सार्क जैसे संगठन सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, पर वह भी निष्क्रिय पड़ा है। चाबहार बंदरगाह जैसे आर्थिक गलियारे भी राजनीति के शिकार हुए हैं। भारत-बांग्ला इंटरनेट कनेक्टिविटी इसका ताज़ा उदाहरण है।

प्रेरणा

भीतर के दीप का प्रकाश: बुद्ध ने बताया चौदहवां रत्न आत्मज्ञान का मार्ग

एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ दूर तक फैले वन पथ पर पदयात्रा कर रहे थे। सूर्य सिर पर था, हवाओं में तपिश थी और सभी अनुयायी थक चुके थे। बुद्ध ने संकेत किया कि अब कुछ देर विश्राम किया जाए। वे सब एक विशाल वटवृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। किसी ने पानी पिया, कोई ध्यान की मुद्रा में बैठ गया, तो कुछ शिष्य बस मौन होकर बुद्ध को निहारने लगे। अचानक आकाश में घने बादल छा गए, हवा में नमी बढ़ी और जंगल के सन्नाटे में हल्का अंधकार फैल गया। इस बदलते माहौल के बीच कुछ शिष्यों के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। तभी एक शिष्य ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर कहा, "प्रभु, आप कहते हैं कि चंद्रमा की चौदह कलाएं होती हैं। क्या उसी प्रकार मनुष्य के भीतर भी चौदह रत्न होते हैं?"

बुद्ध ने शिष्य की ओर देखा, मुस्कराए और बोले, "तेरह रत्न तो हर मनुष्य के भीतर पहले से हैं, जो उसे प्रकृति ने जन्म के साथ ही प्रदान किए हैं। वे हैं — पाँच कर्मेंद्रियां, पाँच ज्ञानेंद्रियां और मन, बुद्धि, अहंकार। ये तेरह तत्व मिलकर मनुष्य के अस्तित्व का ढाँचा बनाते हैं। लेकिन चौदहवां रत्न प्रकृति नहीं देती। वह तुम्हें स्वयं

अर्जित करना पड़ता है।"

शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, "भगवान, वह चौदहवां रत्न क्या है?"

बुद्ध ने अपनी आँखें बंद कर एक गहरी सांस ली और फिर बोले, "वह रत्न है — चित्त। जब तुम्हारा चित्त निर्मल होता है, तभी तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है। यह वही प्रकाश है जो अंधकार को मिटा देता है, भ्रम को तोड़ देता है, मोह को समाप्त कर देता है। चित्त वह दर्पण है जिसमें आत्मा स्वयं को देखती है। जब यह दर्पण धूल-धूसरित हो जाता है, तब व्यक्ति संसार में खो जाता है, लेकिन जब यह निर्मल होता है, तब उसे अपने भीतर का सत्य दिखने लगता है।"

बुद्ध की वाणी सुनकर सभी अनुयायी मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने आगे कहा, "लोग अक्सर बाहर रत्न खोजते हैं — धन, पद, यश, संबंध। लेकिन असली रत्न बाहर नहीं, भीतर है। जो अपने चित्त को पहचान लेता है, वही आत्मा का रत्न पा लेता है। जब भीतर का दीपक जलता है, तो जीवन के हर अंधेरे कोनों में उजाला फैल जाता है। उस क्षण व्यक्ति समझ जाता है कि शांति किसी स्थान, व्यक्ति या वस्तु में नहीं — बल्कि अपने निर्मल चित्त में ही है।"

जंगल में हल्की वर्षा शुरू हो गई थी। बूंदें पत्तों से टकरा रही थीं और वातावरण में एक मधुर संगीत गूंज रहा था। बुद्ध की बातें जैसे हर शिष्य के मन में उतर गईं। सभी मौन बैठे रहे, पर भीतर से वे किसी नई अनुभूति से भर गए थे — जैसे किसी ने उनके हृदय में एक दीपक जला दिया हो।

उस दिन के बाद बुद्ध ने कहा, "जब कभी मन व्याकुल हो, जब अंधकार चारों ओर छा जाए, तो बाहर प्रकाश मत खोजो। आँखें बंद करो, और अपने चित्त के भीतर देखो। वही चौदहवां रत्न तुम्हारे भीतर चमकता है, जो आत्मज्ञान का मार्ग दिखाता है।"

उस पल वन की नीरवता में एक गहरी शांति थी। ऐसा लगा मानो स्वयं प्रकृति भी बुद्ध की वाणी के साथ एकाकार होकर कह रही हो — "जिसने अपने भीतर के चित्त को पहचान लिया, उसने स्वयं भगवान को पहचान लिया।"

भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ सरहदें लांघता जेन-ज़ी आक्रोश

अफ्रीका के मेडागास्कर देश में तख़्तापलट हो गया। जेन-ज़ी आंदोलन ने एक और देश में राजनीतिक तब्दीली करवा दी है। सैन्य तख़्तापलट करने वाले कर्नल माइकल रैंड्रियनिरिना नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले चुके हैं। अगले दो साल सेना सत्ता संभालेगी। आंदोलन के कारण निर्वाचित राष्ट्रपति एंड्री राजोलीना देश छोड़कर भाग गये थे।

मेडागास्कर से पहले नेपाल में भी जेन-ज़ी आंदोलन सत्ता परिवर्तन कराने में सफल हो चुका है। दरअसल एशिया-अफ्रीका-यूरोप के युवा सड़कों पर हैं। वे गुस्से में हैं। ये सारे जेन ज़ी अपने-अपने देशों की सरकारों को हिलाकर, सत्ता में बदलाव चाहते हैं। ये किसी राजनीतिक दल से सीधे-सीधे जुड़े नहीं हैं और न ही इनके बीच कोई बड़ा लीडर है। एशिया के तीन देशों में जेन-ज़ी उभार तख़्तापलट करवा चुका है। ये अलग ही किस्म का राजनीतिक उभार है।

हर देश के जेन-ज़ी आंदोलन में एक बात आम है कि वे बुनियादी मांगों के पूरा न होने पर गुस्से में हैं। तकरीबन हर देश में उनका गुस्सा फूटता है और अपने संग तमाम राजनीतिक ढांचों को बहा ले जाता है। यह भी साफ है कि इस युवा पीढ़ी को मौजूदा राजनीतिक तौर-तरीकों यानी फ्रेमवर्क से अपने मसले हल करने में कोई विश्वास नहीं हैं। जेन-ज़ी युवाओं के भीतर मौजूदा भ्रष्ट सिस्टम के प्रति नाराजगी कुछ समय से पलती रहती है और अचानक कोई ट्रिगर प्वांइट होने पर फट जाता है।

मेडागास्कर से पहले श्रीलंका, बांग्लादेश और हाल में नेपाल में जिस तरह से युवाओं ने सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों के साथ बाकी प्रचलित पार्टियों को किनारे लगाया, वह भी अलग ढंग का राजनीतिक उभार है। सारे जेन-ज़ी विरोधों-प्रदर्शनों के केंद्र में बहुत बुनियादी मांगें हैं- मसलन बेरोजगारी-महंगाई व बेहद भ्रष्टाचार पर गुस्सा, भाई-भतीजावाद पर नाराजगी और खराब सार्वजनिक सेवाओं और बढ़ती गरीबी व असमानता के खिलाफ विद्रोह। लेकिन ये तमाम आंदोलन सत्ता में आमूल-चूल परिवर्तन के बजाय तात्कालिक सत्ता परिवर्तन करने की दिशा अपनाते हैं। इस आंदोलन की पीठ पर सवार होकर सत्ता पर कब्जा करने वाली ताकतों के चेहरे बहुत बाद में सामने आते हैं और उन्हीं के पास नेतृत्व चला जाता है।

अफ्रीका के कई देशों, जैसे दक्षिण अफ्रीका, मोरक्को, नाइजीरिया और केन्या में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और हर जगह कमान युवाओं के हाथ में है। युवा पीढ़ी को मौजूदा राजनीतिक सिस्टम और पार्टियों से दिक्कत है। नेपाल में जैसे नेपो किड्स यानी नेताओं के ऐशो-आराम में डूबे बच्चों पर गुस्सा फूटा था, बेरोजगारी पर उबाल आया था और इसमें रैपर्स, हिप-हॉप गायकों ने अहम भूमिका निभाई, ठीक उसी तरह मोरक्को में युवा आक्रोश सड़कों पर उतरा।

मेडागास्कर में तख़्तापलट की कहानी देखें तो महज कुछ हफ्तों से युवा मौजूदा निज़ाम के खिलाफ पानी और बिजली की कमी, बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ़ सड़कों पर उतरे थे। सरकार ने जब इस आंदोलन की दमन किया, तब सेना की कई यूनिटों ने प्रदर्शनकारियों का साथ दिया। राष्ट्रपति के भागने के बाद कमान सेना ने संभाल ली। हालांकि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस तख़्तापलट को असंवैधानिक बताया और अफ्रीकी संघ ने भी इस कदम को खारिज किया। देश को अब एक सैन्य परिषद चलाएगी और सेना के मुताबिक दो साल के भीतर चुनाव कराए जाएंगे। सवाल है मेडागास्कर में सैन्य तख़्तापलट जेन-ज़ी आंदोलन की अपरिपक्वता का परिणाम है और क्या इससे बाकी देशों में जारी आक्रोश की कोई कड़ी मिलती है।

अफ्रीका के ही एक दूसरे देश- मोरक्को में भी चल रहा है जबर्दस्त आंदोलन। मोरक्को के युवा खुद को जेन-ज़ी 212 कहते हैं। वहां स्वास्थ्य सेवाओं की भयानक हालत और महिलाओं की मौतों ने आक्रोश को भड़काया। युवाओं ने टिकटॉक, इंस्टाग्राम जैसे माध्यमों का इस्तेमाल कर ऑनलाइन समर्थन जुटाया और बड़ी लामबंदी 3 अक्तूबर से शुरू की। आंदोलनकारी कहते हैं कि उनका किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़ाव नहीं है। वे प्रधानमंत्री के इस्तीफे और अपने गिरफ्तार साथियों की रिहाई की मांग लेकर सड़क पर हैं। जेन-ज़ी मोरक्को सरकार की फिजूलखर्ची से नाराज हैं, 2030 में फीफा वर्ल्ड कप के लिए देश भर में भारी लागत से स्टेडियम और लग्जरी होटल बनाए जा रहे हैं, जबकि साधारण नागरिकों के पास न तो अस्पताल हैं और न ही नौकरियां।

सरकार को जनता का पैसा जनता पर ही खर्च करना चाहिए। बुनियादी मांग को लेकर शुरू हुए आंदोलन ने मोरक्को के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। जब उनके आंदोलन का दमन किया गया तब इस विरोध ने उग्र स्वरूप अख्तियार कर लिया।

इसी तरह दक्षिण अफ्रीका में सेवा वितरण और आर्थिक मुद्दों को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। नाइजीरिया और केन्या के युवाओं में भी गुस्सा फूट रहा है। दुनिया भर में जारी जेन-ज़ी आंदोलनों में कॉमन यह है कि युवा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। सेलेब्रिटीज इस आंदोलन से जुड़ते हैं और इसे आगे बढ़ाने में सक्रिय योगदान देते हैं। मोरक्को में हिप-हॉप गायकों व फुटबॉल सितारों ने आंदोलन की मांगों का समर्थन किया।

अभियान

विश्वास और भ्रम के बीच: डिजिटल युग में अंधविश्वास का अनवरत सफर

मानव सभ्यता की यात्रा जितनी प्राचीन है, उतना ही पुराना है अंधविश्वास का साया। यह हमारी संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक मानस में इतनी गहराई से रचा-बसा है कि शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी विकास भी इसे पूरी तरह मिटा नहीं पाए हैं। समय के साथ इसका रूप बदलता गया, पर सार वही रहा — भय, अनिश्चितता और आशा के बीच मनुष्य की वह मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया, जिसे वह "विश्वास" मानता है, पर जो दरअसल तर्क से परे होता है।

प्राचीन काल में अंधविश्वास प्रकृति के प्रति भय और अज्ञान से उपजा। बिजली चमकना, ग्रहण लगना, वर्षा न होना — इन सबका वैज्ञानिक अर्थ समझ न पाने पर मनुष्य ने देवी-देवताओं और अदृश्य शक्तियों के अस्तित्व को स्वीकार लिया। उसने अनुष्ठानों, बलिदानों और प्रतीकों का सहारा लिया ताकि जीवन के अनिश्चित तत्वों पर नियंत्रण पा सके। यही भाव धीरे-धीरे सांस्कृतिक मान्यताओं का हिस्सा बन गया। पीढ़ी दर पीढ़ी यह विश्वास परंपरा बनकर आगे बढ़ा, और फिर परंपरा ही अंधविश्वास में बदल गई।

भारत में अंधविश्वास केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक ढाँचे का भी हिस्सा है। यहाँ अंधविश्वास का आधार न केवल भय है, बल्कि सामूहिक आस्था का वह स्वरूप है जिसमें व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। चाहे काली बिल्ली का रास्ता काटना हो, नींबू-मिर्च टांगना हो या ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर विवाह और निर्माण के निर्णय लेना — ये सब सामाजिक मनोविज्ञान के प्रतीक हैं। परंतु यही प्रतीक तब समस्या बन जाते हैं जब वे निर्णय, स्वतंत्रता और वैज्ञानिक सोच को प्रभावित करने लगते हैं।

आधुनिक युग में जहाँ विज्ञान ने ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाना शुरू किया, वहीं अंधविश्वास ने भी खुद को नए रूप में ढाल लिया। डिजिटल युग ने उसे नया माध्यम दे दिया है। अब वह मंदिरों या तांत्रिकों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मोबाइल ऐप्स, यूट्यूब चैनलों और सोशल मीडिया पोस्टों में बस गया है। "यह मैसेज दस लोगों को भेजो, वरना दुर्भाग्य आएगा" — यह वाक्य आधुनिक अंधविश्वास की सबसे स्पष्ट मिसाल है। यह न कोई परंपरा है, न धर्म — यह मनुष्य की मानसिक असुरक्षा और 'कुछ बुरा न हो जाए' वाले भाव का आधुनिक संस्करण है।

आज लोग अंकशास्त्र के आधार पर मोबाइल नंबर चुनते हैं, घर का नंबर शुभ-अशुभ देखते हैं, लकी रंग, लकी

दिन और लकी समय तय करते हैं। राजनीतिक दल चुनावी तारीख़ शुभ मुहूर्त देखकर घोषित करते हैं, जबकि क्रिकेटर और खिलाड़ी अपने 'लकी बैट' या 'लकी ग्लव्स' के बिना मैदान में उतरने से हिचकते हैं। यह सब दिखाता है कि तर्कशीलता के युग में भी अंधविश्वास ने अपना नया आवरण पा लिया है।

अंधविश्वास का यह विस्तार अब व्यवसाय में भी गहराई से उतर चुका है। बाज़ार में नींबू-मिर्च, ऊर्जा-युक्त रुद्राक्ष, वास्तु अनुकूल पौधे, भाग्यशाली रत्न और एनर्जी क्रिस्टल जैसे उत्पाद करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पर भी 'एनर्जाइज्ड प्रोडक्ट्स' और 'लक चार्म्स' की बिक्री बढ़ती जा रही है। यह आधुनिक युग का 'साइंटिफिक स्पिरिचुअलिज़्म' है, जो विज्ञान और विश्वास के बीच की रेखा को धुंधला करता जा रहा है।

कोविड-19 महामारी इसका चरम उदाहरण रही, जब वैश्विक स्तर पर भय और अनिश्चितता ने मनुष्यों को फिर से अंधविश्वास की ओर धकेला। गोमूत्र, नींबू, ताली-थाली, मंत्र और देवी की आराधना से लेकर झूठे इलाजों तक — सब कुछ वायरल हुआ। यह दिखाता है कि जब विज्ञान और चिकित्सा भी तत्काल समाधान न दे सके, तब मनुष्य फिर उसी पुराने रास्ते पर लौट आता है — विश्वास के नाम पर भ्रम को गले लगाने। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म ने अंधविश्वास को न केवल बढ़ाया, बल्कि उसे गति भी दी। पहले जो बातें मुहल्ले या गाँव तक सीमित थीं, अब वे कुछ सेकंड में विश्वभर में फैल जाती हैं। "अगर यह पोस्ट शेयर नहीं की तो नुकसान होगा", "यह वीडियो देखने से किस्मत चमक जाएगी", "यह रत्न पहनते ही जीवन बदल जाएगा" — ऐसे संदेश आज लाखों लोगों की मानसिकता को प्रभावित करते हैं। इस डिजिटल अंधविश्वास का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह तर्क को मनोरंजन और आस्था के साथ मिला देता है, जिससे भ्रम और बढ़ जाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो अंधविश्वास मनुष्य की सुरक्षा की भावना से जुड़ा है। जब जीवन में नियंत्रण की कमी महसूस होती है, जब भय या असफलता का डर होता है, तब व्यक्ति किसी भी प्रतीक या प्रक्रिया में शक्ति खोजने लगता है। यह उसका मानसिक बचाव है, एक तरह का आत्म-संतोष, जिससे उसे लगता है कि उसने अनिश्चितता पर कुछ नियंत्रण पा लिया है। यही कारण है कि अंधविश्वास पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता — उसे केवल सीमित किया जा सकता है। समाधान का मार्ग केवल शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में है। स्कूलों और समाज में तार्किकता को संस्कृति के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। परंपरा का सम्मान तभी सार्थक है जब वह जीवन को सहज बनाए, न कि उसे भ्रम के दलदल में धकेले। विज्ञान और विश्वास साथ चल सकते हैं, परंतु विज्ञान के स्थान पर विश्वास रख देना सबसे बड़ा खतरा है।

आज जब हम अंतरिक्ष में उपग्रह भेज रहे हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से मशीनों को सोचने सिखा रहे हैं, तब भी अगर कोई काली बिल्ली देखकर रुक जाता है या मैसेज फॉरवर्ड कर "दुर्भाग्य" से बचने की कोशिश करता है, तो यह हमें याद दिलाता है कि अंधविश्वास कोई बीता हुआ अध्याय नहीं, बल्कि हमारी मानसिक यात्रा का वह अधूरा सबक है जो अभी पूरा होना बाकी है।

अंधविश्वास मिटाना विज्ञान का नहीं, चेतना का काम है। जब मनुष्य यह समझ लेगा कि भाग्य नहीं, कर्म ही परिणाम देता है, तब शायद नींबू-मिर्च, लकी नंबर और डिजिटल ताबीज़ों की ज़रूरत नहीं रहेगी — तब मनुष्य अपने भीतर के विश्वास से ही जगमगा उठेगा, और वही सबसे बड़ा प्रकाश होगा।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी के "नागरिक देवो भव" के अभिगम को राज्य में डिजिटल गुड गवर्नेंस के माध्यम से साकार करने की दिशा में GARC की पाँचवीं रिपोर्ट में प्रमुख सिफारिशें

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल को गुजरात प्रशासनिक सुधार आयोग (GARC) की पाँचवीं रिपोर्ट सौंपी गई

- 'एक राज्य –एक पोर्टल' के विज़न के साथ "सरकार नागरिकों के द्वार पर" के सिद्धांत को व्यवहार में उतारने हेतु तैयार की गई सिफारिशों पर आधारित रिपोर्ट
- सिंगल साइन-ऑन सिस्टम (SSO) के माध्यम से एक ही यूज़र आईडी से मिलेंगी नागरिकों को सभी सेवाएँ
- राज्य सरकार की सेवाओं के लिए बार-बार जानकारी देने से मिलेगी मुक्ति, "एक बार जानकारी दें, अनेक बार लाभ पाएं" का लक्ष्य होगा साकार
- डिजिटल गुजरात 2.0 पोर्टल के माध्यम से शासन प्रणाली को प्रोसेस-सेन्ट्रिक से सिटिजन-सेन्ट्रिक रूप में परिवर्तित कर अधिक संवेदनशील सेवा वितरण लागू करने की सिफारिश

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी के 'नागरिक देवो भव' के सिद्धांत को डिजिटल गुड गवर्नेंस के माध्यम से साकार करते हुए, विकसित भारत @2047 के लक्ष्य की दिशा में विकसित गुजरात @2047 से एक नया अध्याय रचने का संकल्प व्यक्त किया है।

उल्लेखनीय है कि इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के प्रशासनिक ढांचे और कार्यप्रणाली में आवश्यक सुधारों के लिए मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार डॉ. हसमुख अढिया की अध्यक्षता में गुजरात प्रशासनिक सुधार आयोग (GARC) का गठन किया है।

अब तक इस आयोग ने राज्य सरकार को चार सिफारिश रिपोर्टें सौंपी हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल को GARC द्वारा 12 प्रमुख सिफारिशों के साथ तैयार की गई पाँचवीं रिपोर्ट सौंपी गई।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी ने डिजिटल तकनीक के व्यापक उपयोग के माध्यम से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का ऐसा विचार देश को दिया है, जिससे नागरिक केंद्रित सेवाएँ सरल, सुगम और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने योग्य बन सकें।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल को सौंपी गई GARC की पाँचवीं रिपोर्ट में इस विचार के अनुरूप "वन स्टेट – वन पोर्टल" (एक राज्य – एक पोर्टल) पहल अपनाने की सिफारिश की गई है। गुड गवर्नेंस के मॉडल स्टेट के रूप में प्रसिद्ध गुजरात में हर नागरिक को एक ही डिजिटल इंटरफेस के माध्यम से सभी सरकारी सेवाएँ एक क्लिक पर उपलब्ध कराने तथा 'गवर्नमेंट ऐट द डोरस्टेप ऑफ सिटिजन' के मंत्र को साकार करने की दिशा में यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

रिपोर्ट में यह भी अनुशंसा की गई है कि सिंगल साइन-ऑन सिस्टम (SSO) के माध्यम से नागरिकों को एक ही यूज़र आईडी से सभी सेवाएँ मिलें। साथ ही, एक बार भरी गई जानकारी को आधार या डिजीलॉकर सेवाओं से जोड़कर विभिन्न सेवाओं में स्वतः उपयोग में लाने की व्यवस्था विकसित की जाए।

इससे नागरिकों को बार-बार वही जानकारी देने से मुक्ति मिलेगी और "एक बार जानकारी दें, अनेक बार लाभ पाएं" का उद्देश्य पूरा होगा।

GARC की इस पाँचवीं रिपोर्ट का मुख्य फोकस डिजिटल गुजरात 2.0 पोर्टल विकसित करने पर है। इसके परिणामस्वरूप प्रशासनिक कार्यप्रणाली पूरी तरह डिजिटल होगी और सरकार व नागरिकों के बीच संवाद और अधिक सुगम बनेगा।

इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि केवल नागरिकों के आवेदन की प्रतीक्षा करने के बजाय उनकी आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाकर स्मार्ट अलर्ट सिस्टम के माध्यम से नागरिकों को उनकी पात्रता के अनुसार सामाजिक कल्याण योजनाओं और लाइफ-साइकल आधारित मार्गदर्शन की जानकारी प्रदान की जाए ताकि एक सक्रिय, नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण प्रणाली लागू हो सके।

रिपोर्ट में प्रमुख नागरिक सेवाओं के लिए एंड-टू-एंड डिजिटल वर्कफ्लो की भी अनुशंसा की गई है। इसमें यह सुझाव दिया गया है कि आवेदन, अनुमोदन और स्थिति अपडेट वास्तविक समय में उपलब्ध हों, जिससे पारदर्शिता, गति और जवाबदेही बढ़े। साथ ही, एक प्रमाणित फॉर्म अपनाकर अनावश्यक दस्तावेज़ों और स्टैम्प्स को समाप्त करते हुए "लेस पेपर-मोर फैसिलिटीज़" के लक्ष्य को साकार किया जाए।

राज्य के सभी जनसेवा केंद्रों (JSK) को आधुनिक बनाने, सेवाओं के लिए प्रतीक्षा समय घटाने, और प्रत्येक केंद्र पर मार्गदर्शन डेस्क स्थापित करने जैसी सिफारिशें भी GARC द्वारा की गई हैं, ताकि सरकार का सिटिजन फर्स्ट दृष्टिकोण और अधिक प्रभावी बने।

रिपोर्ट में यह भी अनुशंसा की गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विलेज कम्प्यूटर ऑन्त्रप्रेन्योर्स (VCEs) की भूमिका को मजबूत किया जाए और शहरी क्षेत्रों में पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के माध्यम से ज़ोन-वाइज़ सेवा वितरण को और तेज बनाया जाए।

आयोग ने राइट टू सिटिजन पब्लिक सर्विस एक्ट के अंतर्गत नागरिक चार्टर के नियमित ऑडिट और अपडेट के लिए एक संरचित प्रक्रिया की सिफारिश की है। साथ ही, जनसेवा केंद्रों में अतिरिक्त स्टाफ पदों की नियुक्ति, कर्मचारियों के प्रशिक्षण और सेवा समय की स्पष्टता जैसी सिफारिशें भी शामिल की गई हैं, ताकि नागरिकों को "ईज़ ऑफ गवर्नेंस" का वास्तविक अनुभव मिल सके।

आयोग के अध्यक्ष डॉ. हसमुख अढिया ने कहा कि यह रिपोर्ट केवल तकनीकी सिफारिशों तक सीमित नहीं है, बल्कि सुशासन की एक नई संस्कृति का प्रतीक है जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी के 'नागरिक देवो भव' के विचार को केंद्र में रखते हुए नागरिकों को शासन की धुरी बनाया गया है।

यह पहल गुजरात को डिजिटल गुड गवर्नेंस के एक नए युग में प्रवेश कराने के साथ-साथ, "सरकार नागरिकों के द्वार पर" के मंत्र को साकार करते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में नागरिक सेवाओं में एक परिवर्तनकारी क्रांति का मार्ग प्रशस्त करेगी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल को GARC की यह पाँचवीं रिपोर्ट सौंपे जाने के अवसर पर मुख्य सचिव श्री पंकज जोशी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री एम. के. दास, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री एस. एस. राठौड़, प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रधान सचिव श्री हरीत शुक्ला, मुख्यमंत्री की अपर प्रधान सचिव श्रीमती अवंतिका सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. विक्रांत पांडे तथा GARC के अधिकारी उपस्थित थे।

GARC की पांचवीं रिपोर्ट की सिफारिशें GARC की वेबसाइट https://garcguj.in/resources पर उपलब्ध हैं।

सोना वायदा में 1497 रुपये और चांदी वायदा में 2460 रुपये का ऊछाल: क्रूड ऑयल वायदा में 16 रुपये का सुधार

कमोडिटी वायदाओं में 34161.49 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 406429.96 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर: सोना-चांदी के वायदाओं में 28296.16 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार: बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 28500 पॉइंट के स्तर पर

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस, इंडेक्स फ्यूचर्स और ऑप्शंस में 440604.16 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 34161.49 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 406429.96 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। इंडेक्स वायदा में 9.91 करोड़ रुपये और इंडेक्स ऑप्शंस में 2.81 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का नवंबर वायदा 28500 पॉइंट के स्तर पर ट्रेड हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 2652.1 करोड़ रुपये का हुआ। कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 28296.16 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना दिसंबर वायदा सत्र के आरंभ में 119647 रुपये के भाव पर खूलकर, 121557 रुपये के दिन के उच्च और 119351 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 119646 रुपये के पिछले बंद के सामने 1497 रुपये या 1.25 फीसदी की मजबूती के साथ 121143 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। गोल्ड-गिनी नवंबर वायदा 1262 रुपये या 1.31 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 97754 रुपये प्रति 8 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-पेटल नवंबर वायदा 156 रुपये या 1.29 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 12230 रुपये प्रति 1 ग्राम पर आ गया। सोना-मिनी दिसंबर वायदा 119700 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 121575 रुपये और नीचे में 119369 रुपये पर पहुंचकर, 1470 रुपये या 1.23 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 121128 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-टेन अक्टूबर वायदा प्रति 10 ग्राम 120200 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 121600 रुपये और नीचे में 119767 रुपये पर पहुंचकर, 121219 रुपये के पिछले बंद के सामने 119 रुपये या 0.1 फीसदी औंधकर 121100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी के वायदाओं में चांदी दिसंबर वायदा 144761 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 147768 रुपये और नीचे में 144618 रुपये पर पहुंचकर, 144342 रुपये के पिछले बंद के सामने 2460 रुपये या 1.7 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 146802 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इनके अलावा चांदी-मिनी

नवंबर वायदा 2418 रुपये या 1.65 फीसदी की तेजी के संग 148795 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि चांदी-माइक्रो नवंबर वायदा 2470 रुपये या 1.69 फीसदी की तेजी के संग 148846 रुपये प्रति किलो हुआ। मेटल वर्ग में 2445.03 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा नवंबर वायदा 7.7 रुपये या 0.76 फीसदी की तेजी के संग 1016.8 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि जस्ता नवंबर वायदा 1.65 रुपये या 0.55 फीसदी बढ़कर 302 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। इसके सामने एल्यूमीनियम नवंबर वायदा 1.1 रुपये या 0.41 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 272.15 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा नवंबर वायदा 5 पैसे या 0.03 फीसदी की नरमी के साथ 183.05 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 3260.30 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल नवंबर वायदा 5311 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 5354 रुपये और नीचे में 5285 रुपये पर पहुंचकर, 16 रुपये या 0.3 फीसदी बढ़कर 5346 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी नवंबर वायदा 15 रुपये या 0.28 फीसदी की मजबूती के साथ 5346 रुपये प्रति बैरल बोला गया। इनके अलावा नैचुरल गैस नवंबर वायदा 341 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 341.9 रुपये और नीचे में 333.5 रुपये पर पहुंचकर, 341.6 रुपये के पिछले बंद के सामने 6.3 रुपये या 1.84 फीसदी औंधकर 335.3 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर आ गया।

जबकि नैचुरल गैस-मिनी नवंबर वायदा 6.2 रुपये या 1.81 फीसदी गिरकर 335.5 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर पहुंचा। कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल नवंबर वायदा 931.4 रुपये पर खूलकर, 1.2 रुपये या 0.13 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 929.4 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 18193.65 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 10102.52 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 1636.47 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 241.78 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 18.82 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 547.40 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 608.44 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 2631.48 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 5.95 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 15408 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 62486 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 19438 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 283355 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 27726 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 27025 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 52814 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 152778 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 17401 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 24547 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स नवंबर वायदा 28743 पॉइंट पर खूलकर, 28743 के उच्च और 27110 के नीचले स्तर को छूकर, 583 पॉइंट बढ़कर 28500 पॉइंट के स्तर पर ट्रेड हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल नवंबर 5300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 10 रुपये की बढ़त के साथ 203.3 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस नवंबर 340 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 3 रुपये की गिरावट के साथ 19.45 रुपये हुआ। सोना अक्टूबर 122000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 347 रुपये की बढ़त के साथ 953 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी नवंबर 150000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 996 रुपये की बढ़त के साथ 4350.5 रुपये हुआ। तांबा नवंबर 1000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 4.21 रुपये की बढ़त के साथ 33.62 रुपये हुआ। जस्ता नवंबर 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 93 पैसे के सुधार के साथ 8 रुपये हुआ। पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल नवंबर 5300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 3 रुपये की गिरावट के साथ 163.8 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस नवंबर 340 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 3.15 रुपये की बढ़त के साथ 24.05 रुपये हुआ। सोना अक्टूबर 115000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 92.5 रुपये की गिरावट के साथ 98 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी नवंबर 140000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 824 रुपये की गिरावट के साथ 2609.5 रुपये हुआ। तांबा नवंबर 1000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 3.08 रुपये की गिरावट के साथ 16.5 रुपये हुआ। जस्ता नवंबर 295 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1 रुपये की गिरावट के साथ 3.5 रुपये हुआ।

वडोदरा मंडल पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन

पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक ने पारदर्शिता के साथ सिस्टम इंप्रूवमेंट पर दिया बल

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल में दिनांक 27 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2025 तक " सतर्कता : हमारी साझा जिम्मेदारी" थीम पर 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' मनाया जा रहा है। इस संबंध में आज पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के मंडल कार्यालय के कांफ्रेंस रूम में सतर्कता जागरूकता पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसे पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक श्री कुलदीप कुमार जैन ने सम्बोधित किया। उन्होंने मंडल के अधिकारियों से भारतीय रेल में सेवाओं एवं कार्य में पारदर्शिता के साथ सिस्टम इंप्रूवमेंट पर जोर दिया।

वडोदरा मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक श्री कुलदीप कुमार जैन वरिष्ठ सतर्कता अधिकारियों के साथ आज वडोदरा मंडल में वडोदरा पधारे। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर मंडल कार्यालय में पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक श्री कुलदीप कुमार जैन के मार्गदर्शन में तथा मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके की अध्यक्षता में सतर्कता जागरूकता मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में श्री जैन ने विभिन्न विभागों में प्रणाली सुधार के क्रियान्वयन की स्थिति पर मंडल के अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की।

इस बैठक से पूर्व पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक श्री जैन ने लोको शेड का निरीक्षण भी किया और शेड के अधिकारियों, सुपरवाइजरों एवं कर्मचारियों के साथ सतर्कता विषय पर काउंसलिंग की।

सतर्कता के बारे में जागरूकता के क्रम में प्रातः मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, प्रतापनगर से साइकिल रैली का आयोजन भी किया गया। इस रैली में पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक श्री कुलदीप कुमार जैन एवं वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके सहित मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दिया।

बिहार चुनाव में धन-बल और बाहुबल का बोलबाला 40 प्रतिशत प्रत्याशी करोड़पति तो 27 प्रतिशत पर गंभीर आपराधिक आरोप

(जीएनएस)। पटना। बिहार विधानसभा चुनाव-2025 एक बार फिर उस पुरानी सच्चाई को सामने ला रहा है कि राज्य की राजनीति में धन और अपराध का गहरा प्रभाव आज भी बरकरार है। एडीआर (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स) और बिहार इलेक्शन वॉच की संयुक्त रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि इस बार चुनाव मैदान में उतरे कुल उम्मीदवारों में से 40 प्रतिशत करोड़पति हैं, जबकि 27 प्रतिशत उम्मीदवारों पर हत्या, बलात्कार और महिलाओं से जुड़े गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, कुल 1,314 उम्मीदवारों के हलफनामों का विश्लेषण किया गया, जिनमें से 519 करोड़पति हैं। इन उम्मीदवारों की औसत घोषित संपत्ति 3.26 करोड़ रुपये पाई गई है। वहीं, लगभग 40 प्रतिशत प्रत्याशी केवल 12वीं तक शिक्षित हैं, जबकि 50 प्रतिशत स्नातक या स्नातकोत्तर हैं। महिला उम्मीदवारों की हिस्सेदारी मात्र 9 प्रतिशत रही, जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व में महिलाओं की सीमित भागीदारी को दर्शाती है। राजनीतिक दलों के स्तर पर देखें तो करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या सभी प्रमुख दलों में अधिक है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने हलफनामे में 11.5 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषित संपत्ति से छह गुना अधिक है। वहीं, दूसरे उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के पास 4.21 करोड़ की संपत्ति है और उनकी पत्नी के नाम पर 7.4 करोड़ रुपये की संपत्ति दर्ज है। पूर्व मंत्री रेणु देवी की संपत्ति 5.5 करोड़ रुपये, प्रेम कुमार की 3.16 करोड़ और डॉ. सुनील कुमार की संपत्ति पाँच साल में बढ़कर 17.5 करोड़ रुपये तक पहुँच गई है। बीजेपी नेता नीरज कुमार सिंह बबलू 11.97 करोड़ की संपत्ति के साथ सबसे धनी प्रत्याशियों में शामिल हैं। सिर्फ धन ही नहीं, बल्कि बाहुबल का असर भी इस चुनाव में गहराई से दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कुल 1,303 उम्मीदवारों में से 423 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जिनमें से 354 पर गंभीर अपराधों के आरोप हैं। इनमें 33 उम्मीदवारों पर हत्या, 86 पर हत्या के प्रयास, और 42 पर महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले दर्ज हैं। यदि पार्टीवार विश्लेषण करें तो स्थिति और भी चिंताजनक दिखती है। सीपीएम के सभी उम्मीदवार (100%) गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं, जबकि भाकपा के 80%, भाकपा (माले) के 64%, राजद के 60%, भाजपा के 56%, और कांग्रेस के 52% उम्मीदवारों के खिलाफ भी गंभीर आरोप हैं। जदयू के 26%, जनसुराज के 43% और बसपा के 18% प्रत्याशी भी किसी न किसी आपराधिक प्रकरण में आरोपित पाए गए हैं। एडीआर की इस रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि पहले चरण के कई प्रत्याशियों के पास लग्जरी गाड़ियाँ, कीमती आभूषण और आधुनिक हथियार हैं। कई प्रत्याशियों के पास सोने-चांदी की ज्वेलरी, निजी सुरक्षा कर्मियों की फौज और दर्जनों वाहनों का बेड़ा है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बिहार की राजनीति में "धनबल और बाहुबल" का गठजोड़ अब चुनावी जीत का अहम आधार बन गया है। यह लोकतंत्र के उस स्वरूप पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है जहाँ मतदाता के सामने विकल्प वही लोग पेश कर रहे हैं जो या तो धन के बल पर राजनीति में टिके हैं या अपराध के दबदबे से अपनी राह बना रहे हैं।

विश्लेषकों का कहना है कि अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मतदाता इन आंकड़ों को कितनी गंभीरता से लेते हैं और क्या वे विकास, शिक्षा और सुशासन जैसे मुद्दों को अपराध और पैसे की राजनीति पर प्राथमिकता देंगे। क्योंकि सवाल सिर्फ चुनावी जीत का नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति की साख और भविष्य का भी है।

31 अक्टूबर से वेरावल-गांधीग्राम के बीच चलेगी दैनिक स्पेशल ट्रेन,टिकटों की बुकिंग 30 अक्टूबर (गुरूवार) से होगी शुरू

(जीएनएस)। जूनागढ़ में लगने वाले परिक्रमा मेले के दरमियान होने वाली यात्रियों की भीड़ एवं उनकी सुविधा को ध्यान में रखकर पश्चिम रेलवे द्वारा विशेष किराये पर वेरावल-गांधीग्राम के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार इन ट्रेनों का विस्तृत विवरण इस प्रकार हैः

ट्रेन नंबर 09226 वेरावल-गांधीग्राम दैनिक स्पेशल ट्रेन वेरावल से रात्रि 21.20 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन सुबह 8.00 बजे गांधीग्राम पहुँचेगी। यह ट्रेन 31.10.2025 से 10.11.2025 तक प्रतिदिन चलेगी।

इसी प्रकार, ट्रेन नंबर 09225 गांधीग्राम-वेरावल दैनिक स्पेशल ट्रेन गांधीग्राम से रात्रि 22.00 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन सुबह 08.45 बजे वेरावल पहुंचेगी। यह ट्रेन

01.11.2025 से 11.11.2025 तक प्रतिदिन चलेगी।

यह ट्रेन मार्ग में मालीया हाटीना, केशोद, जूनागढ़, जेतलसर, विरपुर, गोंडल, भक्तिनगर, राजकोट, सुरेन्द्रनगर जंक्शन, वढवाण सिटी, बोटाद, धंधुका, धोलका, बावला और सरखेज स्टेशनों पर रूकेगी।

इस ट्रेन में थर्ड एसी, स्लीपर और जनरल कोच होंगे। इस ट्रेन के जनरल कोच और एसएलआरडी कोच अनारक्षित होंगे, जिनके लिए टिकट यूटीएस काउंटर से मिलेंगे तथा इन कोचों में सुपरफास्ट मेल/एक्सप्रेस का किराया लगेगा।

ट्रेन नंबर 09226 एवं 09225 के लिए टिकटों की बुकिंग 30.10.2025 (गुरूवार) से यात्री आरक्षण केन्द्रों और आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी। इन ट्रेनों के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

यात्रियों की सुविधा हेतु भावनगर मंडल की 4 जोड़ी ट्रेनों में लगाए जाएंगे दो-दो अतिरिक्त जनरल कोच

(जीएनएस)। यात्रियों की मांग और सुविधा को ध्यान में रखते हुए, पश्चिम रेलवे द्वारा भावनगर मंडल की विभिन्न मार्गों की 4 जोड़ी ट्रेनों में अस्थायी रूप से दो-दो अतिरिक्त जनरल सेकंड क्लास (GS) कोच लगाने का निर्णय लिया गया है। यह व्यवस्था 31 अक्टूबर, 2025 से 10 नवम्बर, 2025 तक प्रभावी रहेगी। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार ट्रेनों का विवरण इस प्रकार हैः-

1.ट्रेन नंबर 19119/19120 वेरावल-गांधीनगर कैपिटल-वेरावल दैनिक एक्सप्रेस

2.ट्रेन नंबर 19207/19208 पोरबंदर-राजकोट-पोरबंदर दैनिक एक्सप्रेस

3.ट्रेन नंबर 59557/59460 भावनगर-पोरबंदर-भावनगर दैनिक पैसेन्जर

4.ट्रेन नंबर 59558/59559 भावनगर-वेरावल-भावनगर दैनिक पैसेन्जर

- यह अस्थायी वृद्धि आगामी त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों की अधिक भीड़ को देखते हुए की गई है, ताकि सभी यात्रियों को यात्रा में सुविधा मिल सके।
- भावनगर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे सुरक्षित यात्रा करें एवं रेलवे द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का लाभ उठाएँ।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के अंतिम चरण में पहुँची बातचीत, जल्द हस्ताक्षर की उम्मीद

(जीएनएस)। सियोल। वैश्विक अर्थव्यवस्था में नई साझेदारी की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी चल रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू में आयोजित एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपीईसी) सीईओ शिखर सम्मेलन के मंच से यह घोषणा की कि भारत और अमेरिका के बीच लंबित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बहुत जल्द हस्ताक्षर किए जाएंगे। ट्रंप ने कहा, "अमेरिका भारत के साथ एक महत्वपूर्ण व्यापार समझौते की ओर बढ़ रहा है और दोनों देश बहुत जल्द इसे औपचारिक रूप देंगे।" उनके इस बयान से यह संकेत मिल रहा है कि अब वर्षों से रुकी यह वार्ता अपने निष्कर्ष की ओर बढ़ चुकी है।

ट्रंप के अनुसार, यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। इस वार्ता में न केवल व्यापारिक रियायतें बल्कि तकनीकी सहयोग, डिजिटल इकॉनमी और बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे कई अहम बिंदु शामिल हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने भारत को कई प्रमुख वस्तुओं पर शुल्क में छूट देने का प्रस्ताव दिया है, वहीं भारत ने अमेरिकी उत्पादों के लिए अपनी बाजार पहुंच के नियमों में कुछ ढील देने पर सहमति जताई है। हालांकि इस समझौते की राह पूरी तरह आसान नहीं रही। रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत द्वारा रूस से कच्चे तेल के आयात को लेकर अमेरिका ने आपत्ति जताई थी। अमेरिकी प्रशासन ने इस पर भारत से आयातित तेल पर 50 प्रतिशत का शुल्क लगाया था, जिसमें से 25 प्रतिशत 'दंडात्मक शुल्क' के रूप में जोड़ा गया था। भारत ने इसे "अनुचित और अविवेकपूर्ण" करार देते हुए कहा था कि ऊर्जा सुरक्षा को लेकर कोई भी देश अपनी नीतियों पर समझौता नहीं कर सकता। इन मतभेदों के बावजूद, बातचीत के पांच दौर सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं। अमेरिकी प्रतिनिधियों के अनुसार, अब दोनों देशों के बीच समझौते का मसौदा लगभग तैयार हो चुका है। समझौते के तहत कृषि, फार्मा, डिजिटल सेवाओं, रक्षा उत्पादों और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। इस समझौते के लागू होने से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार का आकार अगले पांच वर्षों में दोगुना होने की संभावना जताई जा रही है।

भारत की ओर से केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में 'बर्लिन ग्लोबल डायलॉग' के दौरान कहा था कि भारत किसी भी समझौते पर "जल्दबाजी या दबाव में" हस्ताक्षर नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि "भारत अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता किए बिना ही किसी भी वैश्विक व्यापारिक समझौते को स्वीकार करेगा।"

बस्तर में नक्सलवाद पर निर्णायक प्रहार — बीजापुर में 51 माओवादियों ने छोड़ी बंदूक, लोकतंत्र की राह अपनाई

(जीएनएस)। बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल से नक्सलवाद के अंत की दिशा में बुधवार का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ, जब बीजापुर जिले में 51 सक्रिय माओवादियों ने हथियार डालकर मुख्यधारा में लौटने की घोषणा की। आत्मसमर्पण करने वालों में 42 पुरुष और 9 महिलाएं शामिल हैं। इन सभी ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने संविधान पर आस्था व्यक्त करते हुए हिंसा का मार्ग छोड़ने और समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीने की इच्छा जताई।

राज्य सरकार की "पूना मारगेम – पुनर्वास से पुनर्जीवन" योजना और विकास केंद्रित रणनीति का असर अब स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादी लंबे समय से पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए थे। इनमें पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (PLGA) की बटालियन-1, कंपनी नंबर 1, 2 और 5 के सदस्य, एक एरिया कमेटी सदस्य, सात प्लाटून और एरिया कमेटी पार्टी सदस्य, तीन एलओएस सदस्य, एक मिलिशिया प्लाटून कमांडर और 14 मिलिशिया प्लाटून सदस्य शामिल हैं।

इन पर कुल 66 लाख रुपये का इनाम घोषित था। सबसे ज्यादा आठ-आठ लाख रुपये का इनाम बुधराम पोटाम उर्फ रंजीत, मनकी कोवासी, हुंगी सोढ़ी, रवीन्द्र पुनेम उर्फ आयतू और देवे करटाम पर था, जबकि मंगू ओयाम उर्फ लालू पर पांच लाख रुपये का इनाम था। पुलिस का कहना है कि ये सभी माओवादी लंबे समय से नक्सली संगठन में सक्रिय थे और अब सरकार की पुनर्वास नीति से

प्रभावित होकर समाज में लौटना चाहते हैं। आत्मसमर्पण करने वालों को राज्य शासन द्वारा प्रत्येक को 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। पुनर्वास और सामाजिक पुनर्समावेशन की कानूनी प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है।

इस अभियान में जिला रिजर्व गार्ड (DRG), बस्तर फाइटर, विशेष कार्य बल (STF) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) का विशेष योगदान रहा। बीजापुर के पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि यह सफलता केवल सुरक्षा कार्रवाई का परिणाम नहीं, बल्कि शासन की संवेदनशील नीति और जनता के बढ़ते विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य बंदूक नहीं, बदलाव है। सरकार चाहती है कि हर व्यक्ति हिंसा छोड़कर विकास की मुख्यधारा में शामिल हो।"

आंकड़ों पर नज़र डालें तो वर्ष 2025 में अब तक बीजापुर जिले में 461 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जबकि सुरक्षाबलों की कार्रवाई में 138 माओवादी मारे गए और 485 गिरफ्तार हुए हैं। वर्ष 2024 से अब तक जिले में कुल 650 माओवादी मुख्यधारा में लौट चुके हैं। इसी अवधि में 196 माओवादी मुठभेड़ों में मारे गए और 986 को गिरफ्तार किया गया है। ये आंकड़े इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि बस्तर में नक्सलवाद की जड़ें अब पहले की तुलना में काफी कमजोर पड़ चुकी हैं।

पुलिस अधीक्षक यादव ने बताया कि जिन इलाकों में पहले पुलिस का प्रवेश कठिन था, अब वहां सड़कों, स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण तेजी से हो रहा है। ग्रामीण अब विकास कार्यों में खुलकर सहयोग कर रहे हैं और माओवादियों के प्रति विरोध की भावना बढ़ रही है।

हाल के महीनों में बस्तर संभाग के अन्य जिलों में भी बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण हुए हैं। कांकेर में 21, जगदलपुर में 210 और बीजापुर में 103 माओवादियों ने हाल ही में आत्मसमर्पण किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हालिया बस्तर दौरे में घोषणा की थी कि नक्सलवाद को वर्ष 2026 तक देश से पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। उन्होंने माओवादियों से हिंसा का रास्ता छोड़कर लोकतंत्र में विश्वास जताने की अपील भी की थी।

रन फॉर यूनिटी में युवाओं के साथ कदम मिलाएंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी, फतेहाबाद में तैयारियां जोरों पर

(जीएनएस)। फतेहाबाद। देश के लौहपुरुष और आधुनिक भारत की एकता के शिल्पकार सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर 31 अक्तूबर को हरियाणा के फतेहाबाद में राज्य स्तरीय रन फॉर यूनिटी का आयोजन भव्य स्तर पर किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सैनी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे और एकता की इस दौड़ में युवाओं के साथ दौड़ लगाकर उन्हें राष्ट्रीय एकता और समरसता का संदेश देंगे।

कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्य मंच पंचायत भवन के बाहर सड़क के बीचों-बीच बने 15 फुट ऊंचे पुल पर तैयार किया जा रहा है, जहां से मुख्यमंत्री युवाओं को संबोधित करेंगे। डीसी डॉ. विवेक भारती और एसपी सिद्धांत जैन ने बुधवार को मुख्यमंत्री के आगमन से पहले पूरे रूट का निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों ने हैलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक की सुरक्षा, यातायात नियंत्रण, पार्किंग और भीड़ प्रबंधन की विस्तृत समीक्षा की। मुख्यमंत्री नायब सैनी के 30 अक्तूबर की शाम फतेहाबाद पहुंचने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, सीएम के रात्रि भोज का कार्यक्रम गांव फुलां में चेयरमैन वेद फुलां के आवास पर रखा गया है। बुधवार को प्रशासन और खुफिया विभाग के अधिकारियों ने उनके घर का निरीक्षण किया, हालांकि मुख्यमंत्री के आधिकारिक कार्यक्रम की पुष्टि अभी नहीं हुई है। इस राज्य स्तरीय आयोजन में लगभग 15 हज़ार लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है, जिनमें करीब 10 हज़ार विद्यार्थी होंगे। इसके लिए सभी शैक्षणिक संस्थानों को प्रतिभागियों की व्यवस्था का जिम्मा सौंपा गया है। जिला प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि कार्यक्रम में अनुशासन, सुरक्षा और सुचारु यातायात व्यवस्था बनी रहे।

एसपी सिद्धांत जैन ने बताया कि 30 अक्तूबर दोपहर 2 बजे से लेकर 31 अक्तूबर दोपहर 12 बजे तक शहर के मुख्य मार्गों पर यातायात बंद रहेगा। इस दौरान मीनी बाईपास (हिसार चुंगी) से लेकर लघु सचिवालय, पंचायत भवन, लाल बत्ती चौक, पुराना बस अड्डा और नई अनाज मंडी मीनी बाईपास (सिरसा चुंगी) तक वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी जाएगी।

कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने विशेष इंतज़ाम किए हैं। पूरे रूट और आयोजन स्थल पर कुल 17 नाके बनाए गए हैं, जहाँ 7 डीएसपी, 14 इंस्पेक्टर और 1107 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस, होमगार्ड और एनसीसी कैडेट्स को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो।

फतेहाबाद प्रशासन के अनुसार, रन फॉर यूनिटी का उद्देश्य केवल सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देना नहीं है, बल्कि युवाओं को यह संदेश देना है कि भारत की ताकत उसकी विविधता में निहित एकता है। मुख्यमंत्री सैनी के इस दौड़ में शामिल होने से कार्यक्रम के प्रति युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। आयोजन स्थल के आसपास सजावट, रोशनी और देशभक्ति गीतों के साथ माहौल पहले से ही एकता और देशप्रेम की भावना से सराबोर है।

कोलकाता नगर निगम भर्ती घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई — व्यापारी के ठिकानों पर छापा, 1.2 करोड़ रुपये नकद जब्त, राजनीतिक हलचल तेज

(जीएनएस)। कोलकाता। पश्चिम बंगाल में भर्ती घोटालों की कड़ी अब नगर निगम तक पहुँच गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कोलकाता में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दक्षिण कोलकाता के तारातला इलाके में एक व्यापारी के घर और दफ्तरों पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान एजेंसी ने 1.2 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी बरामद की है। साथ ही कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और खातों से जुड़े रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं।

सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई मंगलवार देर रात शुरू हुई थी और बुधवार सुबह तक जारी रही। ईडी की विशेष टीम ने छापेमारी के दौरान कारोबारी से जुड़े आर्थिक लेन-देन की विस्तृत जांच की। एजेंसी को संदेह है कि नगर निगम भर्ती घोटाले में इस व्यापारी की भूमिका संदिग्ध है और उसके खातों से कई अवैध लेन-देन के सबूत मिले हैं। ईडी के सूत्रों का कहना है कि यह छापेमारी नगर निगम भर्ती घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की परतों को उजागर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जांच में सामने आया है कि निगम में विभिन्न पदों पर नियुक्तियों के लिए दलाली और घूस के माध्यम से बड़े पैमाने पर रकम का आदान-प्रदान हुआ था। एजेंसी का अनुमान है कि करोड़ों रुपये की अवैध राशि फर्जी कंपनियों और शेल अकाउंट्स के जरिए सफेद की गई।

छापेमारी केवल तारातला तक सीमित नहीं रही। ईडी ने शहर के बेलेघाटा, बेंटिक स्ट्रीट और पार्क स्ट्रीट क्षेत्रों में भी एक साथ तलाशी अभियान चलाया। बेलेघाटा स्थित "लक्ष्मी रामलया" नामक आवास पर बुधवार सुबह करीब 7 बजे छह सदस्यीय टीम ने दबिश दी। घर के अंदर तलाशी के दौरान भारी मात्रा में कैश, सोने के आभूषण और कुछ विदेशी मुद्रा भी मिली है।

ईडी अधिकारियों ने बताया कि यह नेटवर्क नगर निगम भर्ती घोटाले का "फाइनेंशियल बैकबोन" है — जिसके जरिए घूस की रकम इकट्ठा कर उसे कई स्तरों पर बांटा जाता था। एजेंसी ने इस मामले में कई बैंक खातों को फ्रीज़ कर दिया है और कुछ रियल एस्टेट फर्मों की लेन-देन गतिविधियों पर भी निगरानी रखी जा रही है।

इससे पहले इसी केस में राज्य के मंत्री सुजीत बोस और उनके करीबी सहयोगियों के ठिकानों पर भी ईडी ने छापेमारी की थी। एजेंसी को संदेह है कि नगर निगम और पालिकाओं में नियुक्तियों में भी वही पैटर्न अपनाया गया जो शिक्षक भर्ती घोटाले में देखा गया था — जहां पैसे लेकर फर्जी नियुक्तियाँ दी गईं। ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक, नगर निगम में सफाई कर्मियों से लेकर इंजीनियरों तक की नियुक्ति में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। प्रत्येक पद के लिए "रेट कार्ड" तय था और रकम बिचौलियों के माध्यम से नेताओं और अफसरों तक पहुँचाई जाती थी। एजेंसी को कई ऐसे व्हाट्सएप चैट और ईमेल ट्रेल्स मिले हैं जो घूसखोरी के प्रमाण के रूप में काम आ सकते हैं। इस कार्रवाई ने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने केंद्र सरकार पर "राजनीतिक बदले की कार्रवाई" का आरोप लगाया है, जबकि भाजपा ने इसे "भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार" बताया है। भाजपा प्रवक्ता सामिक भट्टाचार्य ने कहा, "राज्य की जनता अब समझ चुकी है कि नौकरी बेचने का कारोबार किस हद तक फैला था। ईडी की कार्रवाई जनता के विश्वास की पुनर्स्थापना है।" दूसरी ओर, राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि ईडी को कानून की सीमा में रहकर ही काम करना चाहिए और निर्दोष नागरिकों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। ईडी सूत्रों के अनुसार, आने वाले दिनों में और भी छापे और गिरफ्तारियाँ संभव हैं। एजेंसी इस घोटाले से जुड़े सभी फाइनेंशियल ट्रेल्स को खंगाल रही है और उन खातों की जांच कर रही है जिनसे "घूस की रकम" को आगे बढ़ाया गया। केंद्र सरकार इस कार्रवाई को नगर निकायों में पारदर्शिता और सुशासन की दिशा में "सिस्टम की सफाई अभियान" के रूप में देख रही है। पश्चिम बंगाल में यह मामला अब केवल भ्रष्टाचार का नहीं, बल्कि व्यवस्था की साख से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। और अगर ईडी की जांच ने यह साबित कर दिया कि सरकारी नौकरियाँ खुलेआम बेची जा रही थीं, तो यह राज्य की राजनीति के लिए आने वाले दिनों में एक बड़ा विस्फोटक मोड़ साबित हो सकता है।

आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर पर सीबीआई का शिकंजा

(जीएनएस)। नई दिल्ली/चंडीगढ़। पंजाब पुलिस के उप महानिरीक्षक (DIG) हरचरण सिंह भुल्लर पर भ्रष्टाचार और अवैध संपत्ति के आरोपों की जांच गहराती जा रही है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने अब भुल्लर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का एक नया मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई उस रिश्वत प्रकरण के बाद की गई है, जिसमें उन्हें 16 अक्टूबर को एक बिचौलिए के साथ पांच लाख रुपये की घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया था। सीबीआई सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तारी के बाद चंडीगढ़ के सेक्टर 40बी स्थित मकान संख्या 1489 पर छापेमारी की गई, जहाँ जांच एजेंसी को 7.36 करोड़ रुपये नकद, 2.32 करोड़ रुपये मूल्य के सोने-हीरे के आभूषण, 26 महंगी ब्रांडेड घड़ियाँ और परिवार के नाम पर अचल संपत्तियों के दस्तावेज मिले। एजेंसी ने बताया कि ये संपत्तियाँ भुल्लर, उनकी पत्नी तेजिंदर कौर, बेटे गुरप्रताप सिंह और बेटी तेजकिरण कौर के नाम पर खरीदी गईं। प्राथमिकी में यह खुलासा हुआ है कि भुल्लर और उनके परिवार ने मोहाली, लुधियाना और होशियारपुर जिलों में करीब 150 एकड़ कृषि भूमि और कई व्यावसायिक संपत्तियाँ

खरीदीं। सीबीआई को यह भी पता चला कि उनके परिवार के पास मर्सिडीज, ऑडी, फॉर्च्यूनर और इनोवा जैसी लग्जरी गाड़ियाँ हैं। जांच में सामने आया कि परिवार के नाम पर पांच बैंक खाते और दो सावधि जमा में करीब 2.95 करोड़ रुपये जमा हैं। सीबीआई ने भुल्लर की आयकर रिटर्न की भी जांच की, जिसके अनुसार उन्होंने 2025-26 के लिए कुल वार्षिक आय केवल 45.95 लाख रुपये घोषित की थी। लेकिन जब्त नकदी, संपत्तियों और गहनों की कीमत इसके मुकाबले कई गुना अधिक पाई गई। एजेंसी ने आरोप लगाया कि यह धन अवैध रूप से अर्जित किया गया है और यह भुल्लर की ज्ञात आय के स्रोतों से मेल नहीं खाता। जांच में यह भी पाया गया कि भुल्लर अपने खिलाफ जब्त की गई संपत्तियों के बारे में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में असफल रहे। सीबीआई का कहना है कि इस पूरे प्रकरण में उनके परिवार के सदस्यों की भूमिका की भी जांच की जाएगी, क्योंकि उन्होंने संभवतः अवैध संपत्ति अर्जित करने में उनकी मदद की। भुल्लर पर लगे आरोप न केवल पंजाब पुलिस के लिए बल्कि राज्य की कानून व्यवस्था की साख के लिए भी गंभीर झटका माने जा रहे हैं। सीबीआई अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में संपत्ति के स्रोतों की फॉरेंसिक जांच की जाएगी और यह पता लगाया जाएगा कि पैसा किन माध्यमों से निवेश किया गया। पंजाब पुलिस के इतिहास में यह मामला उन गिने-चुने मामलों में से एक बन गया है, जहाँ एक उच्च पदस्थ अधिकारी पर एक साथ रिश्वत और आय से अधिक संपत्ति के मामले दर्ज हुए हैं। सीबीआई ने साफ कहा है कि यह मामला केवल भ्रष्टाचार नहीं बल्कि 'संरचित धन-शोधन नेटवर्क' का संकेत देता है। आने वाले दिनों में एजेंसी द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने और संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई भी संभव है।

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और लद्दाख प्रशासन को भेजा नोटिस

(जीएनएस)। नई दिल्ली। पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन को नोटिस जारी किया है। अदालत ने दोनों पक्षों से 10 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह मामला केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पीठ — न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया — ने कहा कि अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी, जिसमें वांगचुक की गिरफ्तारी की वैधता और एनएसए के तहत की गई कार्रवाई की संवैधानिकता की गहराई से जांच की जाएगी। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. अंगमो ने शीर्ष अदालत में संशोधित याचिका दायर कर यह दावा किया कि उनके पति को गैरकानूनी रूप से हिरासत में लिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह गिरफ्तारी दरअसल लद्दाख के लोगों की आवाज़ को दबाने और राज्य का दर्जा व संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को कमजोर करने का प्रयास है। सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को लद्दाख आंदोलन के दौरान एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के तहत गिरफ्तार किया गया था। प्रशासन का आरोप है कि उन्होंने अपने भाषणों से लोगों को हिंसा के लिए उकसाया, जिसके बाद हुए संघर्ष में चार लोगों की मौत और 90

से अधिक घायल हुए। गिरफ्तारी के बाद उन्हें जोधपुर जेल भेजा गया, जहां वे इस समय बंद हैं। याचिका में यह भी कहा गया कि वांगचुक के परिवार को उनसे मिलने में कठिनाई हो रही है और उन्हें जेल में एकांत में रखा गया है। हालांकि, सरकार की ओर से दायर रिपोर्ट में कहा गया कि उनके भाई और वकील उनसे मुलाकात कर चुके हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत से गुजारिश की कि वांगचुक को अपनी पत्नी के साथ लिखित नोट्स साझा करने की अनुमति दी जाए। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। गौरतलब है कि एनएसए एक ऐसा कड़ा कानून है, जिसके तहत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है, अगर सरकार यह मानती है कि वह "राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा" है। कई मानवाधिकार संगठन इस कानून को दमनकारी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ बताते रहे हैं। लद्दाख में इस मामले को लेकर माहौल लगातार गर्म है। सोनम वांगचुक को वहां के लोग "लद्दाख की आवाज़" कहकर संबोधित कर रहे हैं और उनकी रिहाई के लिए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी हैं। लेह और कारगिल दोनों जिलों में सामाजिक संगठनों और मठों ने शांतिपूर्ण धरने शुरू कर दिए हैं। अब सबकी निगाहें 24 नवंबर को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जब सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि सोनम वांगचुक जेल में रहेंगे या उन्हें न्यायिक राहत मिल सकेगी। लद्दाख के लोगों के लिए यह सुनवाई सिर्फ एक व्यक्ति की आज़ादी नहीं, बल्कि अपनी आवाज़ की आज़ादी का सवाल बन गई है।

लखनऊ में बुजुर्ग से 38 लाख की साइबर ठगी, ठगों ने 'डिजिटल अरेस्ट' का डर दिखाकर उड़ाए पैसे

(जीएनएस)। लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में साइबर अपराधियों ने एक बेहद चौंकाने वाला मामला अंजाम दिया है। ठगों ने खुद को सरकारी अधिकारी बताकर एक बुजुर्ग को "डिजिटल अरेस्ट" के नाम पर डरा-धमकाकर पूरे 38 लाख रुपये ठग लिए। मामला जानकीपुरम गार्डन इलाके का है, जहां रहने वाले अश्विनी कुमार गुप्ता नामक बुजुर्ग को 30 सितंबर को एक अज्ञात नंबर से कॉल आया, जिसने उनकी ज़िंदगी की शांति छीन ली। कॉलर ने खुद को "मुंबई क्राइम ब्रांच" का अधिकारी बताया और कहा कि उनके आधार कार्ड का इस्तेमाल हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग में हुआ है। उसने बुजुर्ग को धमकाते हुए कहा कि उनके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है और अब उन्हें अपनी संपत्ति और बैंक खातों की पूरी जानकारी देनी होगी।

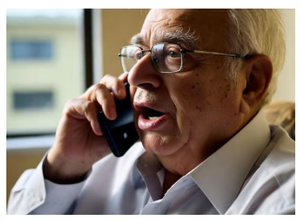

कॉलर ने उन्हें व्हाट्सएप पर नकली दस्तावेज और सरकारी मुहरों वाले फर्जी पत्र भेजे, जिससे गुप्ता को भरोसा हो गया कि मामला असली है। इसके बाद ठगों ने कहा कि जांच पूरी होने तक उनके सभी बैंक खातों की राशि "सुरक्षित खाते" में ट्रांसफर करनी होगी, नहीं तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। डर और घबराहट में आकर बुजुर्ग ने 14 अक्टूबर को अपने एसबीआई जानकीपुरम ब्रांच से 24.70 लाख रुपये आरटीजीएस के जरिए ठगों के बताए खाते में भेज दिए।

लेकिन यहीं बात खत्म नहीं हुई। दो दिन बाद ठगों ने फिर संपर्क कर कहा कि अब "एनओसी जारी करने" के लिए कुछ और रकम जमा करनी होगी। गुप्ता ने इस बार पेंशन लोन लेकर 13.72 लाख रुपये और भेज दिए। इस तरह उनके दो खातों से कुल 38.42 लाख रुपये ठगों ने हड़प लिए। जब तीसरी बार पैसे मांगे गए तो गुप्ता को शक हुआ। उन्होंने तुरंत साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने अब इस मामले की जांच शुरू कर दी है और ट्रांजैक्शन के जरिए ठगों के खातों को ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। यह मामला मुंबई क्राइम ब्रांच और चेन्नई डीजीपी कार्यालय को भी भेजा गया है क्योंकि कॉलर वहीं के नाम से ठगी कर रहे थे।

साइबर सेल के अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के "डिजिटल अरेस्ट" मामलों में ठग पहले सरकारी अफसर बनकर डर पैदा करते हैं और फिर धीरे-धीरे व्यक्ति से आर्थिक जानकारी लेकर खाते खाली कर देते हैं।

अधिकारियों ने लोगों को चेताया है कि कोई भी सरकारी एजेंसी फोन या व्हाट्सएप के जरिए बैंक डिटेल, आधार नंबर या पैसे की मांग नहीं करती। अगर किसी को भी ऐसे कॉल आते हैं तो 155260 या 1930 पर तुरंत शिकायत करें और cybercrime.gov.in पोर्टल पर जानकारी दें।

सरकार और पुलिस ने दोहराया है कि ऐसे कॉल्स पर डरने की बजाय सतर्क रहें, क्योंकि अब साइबर अपराधी "डिजिटल गिरफ्तारी" जैसे नए जाल बिछाकर सीधे लोगों की मेहनत की कमाई पर हाथ डाल रहे हैं।

दादरी में सनसनीः डीयू छात्रा ने पिता पर लगाया दुष्कर्म के प्रयास का आरोप, पुलिस ने दर्ज की FIR

(जीएनएस)। गौतम बुद्ध नगर। दीपावली की खुशियों के बीच दादरी क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा ने अपने ही पिता पर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया है। आरोपों के मुताबिक, जब छात्रा की मां रसोई में व्यस्त थीं, तभी पिता ने उसे कमरे में बंद कर अनुचित हरकत करने की कोशिश की। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

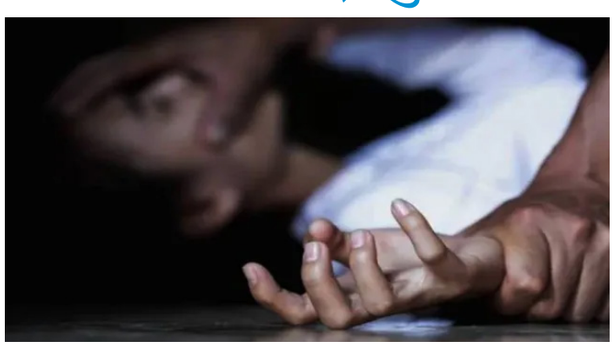

पीड़िता, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में बीए की छात्रा है, ने अपनी शिकायत में बताया कि यह पहली बार नहीं है जब उसके पिता ने इस तरह की हरकत की हो। उसने आरोप लगाया कि बचपन से ही उसका पिता उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता रहा है। जब वह छोटी थी, तो उसकी मां ने उसे इस माहौल से दूर रखने के लिए मेरठ स्थित मामा के घर भेज दिया था, जहां से उसने बारहवीं तक की पढ़ाई पूरी की। पीड़िता ने बताया कि वह 21 अक्टूबर को दीपावली मनाने के लिए अपने घर दादरी आई थी। उसी रात जब उसकी मां रसोई में व्यस्त थीं, तभी उसके पिता ने मौका पाकर उसे कमरे में बंद कर दिया और जबरदस्ती की कोशिश की। छात्रा के चिल्लाने पर मां तुरंत पहुंचीं और बेटी को वहां से बाहर निकाला। आरोपी पिता मौके से फरार हो गया। घटना के बाद मां-बेटी कुछ दिनों तक भय और सामाजिक लोकलज्जा के कारण चुप रहीं। बाद में साहस जुटाकर पीड़िता ने दादरी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के मीडिया प्रभारी ने बताया कि आरोपी पिता फिलहाल फरार है और पुलिस उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे महिला थाना और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग यूनिट को भी भेजा गया है ताकि पीड़िता को मनोवैज्ञानिक सहायता मिल सके। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि यह मामला बेहद संवेदनशील है और जांच पूरी पारदर्शिता और तत्परता से की जा रही है।

दादरी जैसे शांत क्षेत्र में इस घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। समाजसेवी संगठनों ने प्रशासन से आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा दिलाने की मांग की है।